10 लोग घायल हुए हैं पाकिस्तान में रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में धमाका होने से। इसी अस्पताल में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर भी भर्ती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान उल्ला ने रविवार को ट्वीट कर यह दावा किया है।

पाकिस्तान को कतर से मिला 21 हजार करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज

इस्लामाबाद, प्रेट्र : आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद को अब तेल संपन्न राष्ट्र कतर सामने आया है। इस खाड़ी देश से पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर (करीब 21 हजार करोड़ रुपये) का बेलआउट पैकेज मिलना सोमवार को पक्का हो गया। इस एलान से एक दिन पहले ही कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद ने इस्लामाबाद का दौरा किया था।

पाक को आर्थिक बदहाली से उबारने के लिए पिछले 11 माह में सामने आने वाला कतर चौथा देश है। इमरान खान ने पीएम बनने के बाद आर्थिक मदद पाने के प्रयास में खाड़ी देशों के साथ चीन का दौरा किया था। कतर के विदेश मंत्री शेख मुहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने इस मदद का एलान किया। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी ने एक ट्वीट में कहा, 'अमीर के आदेश पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जमा और प्रत्यक्ष निवेश के तौर पर पाक में तीन अरब डॉलर का नया निवेश करने का एलान किया है।'

शेख तमीम बिन हमाद और इमरान खान। फाइल

इमरान के सलाहकार ने जताया आभार

इमरान खान के वित्तीय सलाहकार अब्दुल शेख ने कतर से आर्थिक मदद मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मैं तीन अरब डॉलर के निवेश का एलान करने के लिए शेख तमीम बिन हमाद का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।'

अब तक इतनी मिली मदद

- चीन ने जमा और वाणिज्यिक कर्ज के तौर पर 4.6 करोड़ डॉलर दिए
- सऊदी अरब ने तीन अरब डॉलर नकद और 3.2 अरब डॉलर का तेल दिया
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से दो अरब डॉलर नकद मिला

आइएमएफ के पैकेज पर सहमति

छह अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) और पाकिस्तान के बीच पिछले माह प्रारंभिक समझौता हो चुका है। उम्मीद है कि इस पैकेज से पाकिस्तान की धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और घोर आर्थिक संकट से निपटने में सहायता मिलेगी।

तालिबान ने अफगान मीडिया को धमकाया

काबुल, एपी: आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान के मीडिया संस्थानों को धमकी दी है कि वह अब पत्रकारों को निशाना बनाएगा। सोमवार को तालिबान की ओर से कहा गया कि मीडिया संस्थानों से जुड़े लोग तालिबान के विरुद्ध चलाए जा रहे सरकारी दुष्प्रचार व संदेश को अगर फौरन बंद नहीं करते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तालिबान ने पत्रकारों को सुधर जाने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है।

देश में आतंकियों द्वारा जारी हमलों को देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार रेडियो, टीवी और अन्य मीडिया संस्थानों के जरिये स्थानीय लोगों के लिए संदेश प्रसारित करा रही है। संदेश में लोगों को किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों की भनक लगने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की सलाह दी गई है। इससे बौखलाए तालिबान ने स्थानीय मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी है।

धमकी में कहा गया है कि फरमान की अवहेलना करने वाले पत्रकारों को तालिबान दुश्मन माना जाएगा और उन्हें उचित सजा दी जाएगी। बता दें कि आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान के साथ-साथ पाक में भी आतंकी वारदात को अंजाम देता है।

जी-20 में हांगकांग मसला नहीं उठने देगा चीन

- 27-28 जून को जापान में होगी समूह-20 के सदस्य देशों की बैठक
- अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की है हांगकांग पर चर्चा की तैयारी
- चीन ने कहा - आंतरिक मामलों में बोलने का किसी को हक नहीं

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने कहा है कि वह इस हफ्ते होने जा रही जी-20 देशों की बैठक में हांगकांग के मसले पर चर्चा की अनुमति नहीं देगा। एक विवादित प्रत्यर्पण कानून को लेकर हाल में हांगकांग में लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अन्य सदस्य देशों के समक्ष यह मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं।

जी-20 देशों का सम्मेलन 27-28 जून को जापान के ओसाका में होगा। चीन ने कहा है कि वह सम्मेलन के दौरान हांगकांग का मुद्दा उठाने की अमेरिका समेत किसी भी देश की कोशिश का विरोध करेगा। चीन के सहायक विदेश मंत्री झांग जून ने कहा कि जी-20 वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का मंच है। हांगकांग चीन का विशेष क्षेत्र है और किसी भी दूसरे देश को इसके मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि हांगकांग में पिछले दिनों एक विवादित प्रत्यर्पण विधेयक पेश किया गया था। इसके तहत आरोपितों को चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान था। इस विधेयक के विरोध में यहां जबर्दस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। इस विधेयक और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों

शी चिनफिंग। फाइल

ने आलोचना की थी। ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के बाद हांगकांग की सरकार ने विधेयक पर रोक लगा दी थी। हांगकांग की नेता कैरी लेम ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह के चर्चा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। हालांकि प्रदर्शनकारी विधिवत रूप से कानून में बदलाव के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

पीएम मोदी, शी और पुतिन करेंगे वार्ता

बीजिंग, प्रेट्र : जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और समूह के कुछ अन्य नेता अमेरिका की एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों और संरक्षणवाद की नीति पर अलग से चर्चा करेंगे। चीन के एक वरिष्ठ मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ट्रंप व्यापार और प्रशुल्क को केवल अमेरिकी हित को प्राथमिकता देने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

जी20 शिखर सम्मेलन इसी सप्ताह जापान के ओसाका शहर में 28-29 जून को होने जा रहा है। राष्ट्रपति शी वहां एक दिन पहले पहुंचने वाले हैं। वह वहां ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के नेताओं से बातचीत में अमेरिकी संरक्षणवाद का मुद्दा विस्तार से उठा सकते हैं। मोदी, शी और पुतिन अभी पिछले दिनों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के समय भी मिले थे।

अमेरिका ने ईरान पर लगाए कड़े प्रतिबंध

तनातनी जारी ▶ कार्यकारी आदेश पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर

कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर पर भी होगा असर, बढ़ाते जाएंगे दबाव

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगेंगे और अमेरिकी क्षेत्र में तेहरान के सुप्रीम लीडर और दूसरे अधिकारी बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ट्रंप ने यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब कुछ दिन पहले ही ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को अपने इलाके में होने का दावा करते हुए मार गिराया था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी हमले का आदेश भी दे दिया था पर उन्होंने कहा कि इससे 150 लोगों की जान जाती इसलिए अपने आदेश को 10 मिनट पहले उन्होंने वापस ले लिया।

सोमवार को अपने ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम ईरान या किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि हम कभी भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे द्वारा काफी संयम दिखाया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।' ट्रंप ने कहा है कि वह आगे भी तेहरान पर दबाव बढ़ाते जाएंगे। पत्रकारों ने पूछा कि क्या यह कार्यकारी आदेश अमेरिकी ड्रोन पर ईरान के हमले का जवाब है? इस पर ट्रंप ने कहा, 'आप इसे भी जोड़ सकते हैं।' हालांकि उन्होंने आगे कहा कि यह तो हर हाल में होना था।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं कई ईरानियों को जानता हूं जो न्यू यॉर्क में रहते हैं और वे शानदार लोग हैं।' इससे पहले, ईरान मामलों पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से प्रतिबंध हटाने को लेकर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ईरान को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रोकने होंगे।

प्रतिबंधों के साये में बातचीत बेमतलब : बातचीत के सवाल पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के सलाहकार हसमोदीन आशना ने कहा, 'खतरों और प्रतिबंधों के साए में बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार अमेरिका के दावे का कोई मतलब नहीं है। हमारा मानना है कि प्रतिबंध भी युद्ध का दूसरा पहलू है।' हालांकि अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों में छूट की स्थिति में ईरान ने भी बातचीत का संकेत दिया है। अमेरिका की ओर से नए प्रतिबंधों को भी ईरान ने निरर्थक कहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसवी ने कहा, 'क्या अभी ऐसा कोई प्रतिबंध बचा भी है, जो अमेरिका ने हाल में या पिछले 40 साल में ईरान पर नहीं लगाया? हम नहीं जानते कि अब कौन सा नया प्रतिबंध लगेगा। हमें लगता है कि इन प्रतिबंधों से कोई अलग असर नहीं पड़ने वाला है।'

हसन रूहानी

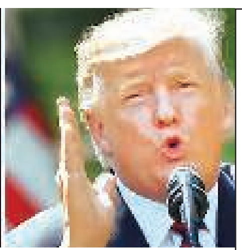
डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

ट्रंप ने कहा, अपने तेल की रक्षा खुद करें

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों से कहा है कि वे खाड़ी के रास्ते आने-जाने वाले अपने तेल टैंकरों की हिफाजत खुद करें। उन्होंने कहा, 'अमेरिका खुद ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। इसलिए हम क्यों बिना किसी फायदे के अन्य देशों के तेल टैंकरों की हिफाजत कर रहे हैं। इन सभी देशों को खुद अपने टैंकरों की रक्षा करनी चाहिए, जिनका सफर हमेशा डर के साए में होता है।' अमेरिका के इस फैसले के बाद अन्य देशों की चिंता बढ़ जाएगी।

सऊदी पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री

जेद्दा, एएफपी : अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ ईरान संकट पर बातचीत के लिए सोमवार को जेद्दा पहुंचकर सऊदी अरब के शाह सलमान से उनके महल में मुलाकात की। अमेरिकी निगरानी ड्रोन को ईरान द्वारा मार गिराए जाने के बाद पोंपियो एक दिन के जेद्दा दौरे पर यहां पहुंचे थे

शाह ने शीर्ष अमेरिकी राजनयिक और उनके सहयोगियों से हाथ मिलाया और पोंपियो से कहा कि आप एक करीबी मित्र हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पोंपियो सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद वह संयुक्त अरब अमीरात रवाना होंगे।

बता दें कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेता ईरान के खिलाफ अमेरिका के कड़े रुख का समर्थन करते हैं। ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन गिरा दिए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने हमले का विचार त्याग दिया था। पोंपियो ने वाशिंगटन से रवाना होते समय पत्रकारों से कहा कि ईरान द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों का सामना करने में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दो महान सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हम रणनीतिक रूप से एक साथ हैं और किस तरह हम एक वैश्विक संगठन बना सकते हैं।

पाक में मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी के लिए लेनी होगी अनुमति

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी करने के लिए मध्यस्थता परिषद की अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसा उन्हें तब भी करना होगा जब उन्हें इसके लिए पहली पत्नी से अनुमति मिल चुकी हो। कोर्ट ने यह आदेश लियाकत अली मीर से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मीर ने 2011 में प्रेम विवाह किया था और बिना पहली पत्नी और मध्यस्थता परिषद की अनुमति के 2013 में दोबारा विवाह कर लिया था।

जियो टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनउल्लाह ने अपने 12 पेज के लिखित आदेश में कहा है कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी के लिए मध्यस्थता परिषद की अनुमति लेना आवश्यक है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चल रहे पहले विवाह के दौरान अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे प्रक्रिया का पालन करना होगा और कानून द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर दोषी व्यक्ति को कैद और आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक मौजूदा विवाह के निर्वाह के दौरान कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता परिषद की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य विवाह का अनुबंध नहीं कर सकता है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में बहुविवाह की प्रथा के समर्थकों को झटका लग सकता है।

महिला अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एड पर विवाद

इस्लामाबाद, एएफपी : पाकिस्तान में रूढ़िवादियों को एक अंतरराष्ट्रीय डिटरजेंट का विज्ञापन सिर्फ इसलिए रास नहीं आया, क्योंकि उसमें महिला अधिकारों को बढ़ावा दिया गया था। आलोचकों का कहना है कि यह विज्ञापन इस्लाम का अपमान करने वाला है। अमेरिका के प्राक्टर एंड गैंबल के स्वामित्व वाले एरियल डिटरजेंट में महिलाओं से आह्वान किया गया है कि वे रूढ़िवादी तौर-तरीकों को तोड़ें और अपने कॅरियर को आगे बढ़ाएं। विज्ञापन का अंत पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिसमाह मारूफ के एक क्लोज-अप शॉट से होता है, जिसमें मारूफ कहती हैं-घर के भीतर रहो...यह केवल वाक्य नहीं, बल्कि दाग है। इस विज्ञापन को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बवाल मच गया। कट्टरपंथी इस विज्ञापन पर हैशटैग बायकाटएरियल के साथ बरस पड़े। ट्विटर पर बिंट सुलेमान ने लिखा-विज्ञापन में इस्लाम का अपमान किया गया है, जबकि एक अन्य यूजर राजा मोअज्जम ने लिखा-इन उदारवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने पाकिस्तान के नियामकों से अपील की कि इस विज्ञापन पर पाबंदी लगाई जाए।

सऊदी एयरपोर्ट पर हाउती विद्रोहियों ने किया ड्रोन से हमला

रियाद, रायटर : यमन के हाउती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ड्रोन से किए गए हमले में एक सऊदी नागरिक के मारे जाने और 21 के घायल होने की खबर है। ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा है। जबकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना 2015 से ही उनसे मुकाबला कर रही है।

सऊदी सरकारी टेलीविजन ने गठबंधन सेना के हवाले से कहा, 'ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर से आभा एयरपोर्ट पर ड्रोन से आतंकी हमला किया गया। इसमें एक सीरियाई नागरिक की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हुए।' इससे पहले हाउती समर्थित अल-मसिराह टीवी ने सऊदी के आभा और जिजान एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया था। हालांकि जिजान एयरपोर्ट पर हमले की पुष्टि नहीं हो पाई। सऊदी अरब के अल-अरबिया टीवी ने बताया कि उत्तरी यमन की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर आभा एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में ड्रोन से हमला किया गया था।

हाउती विद्रोहियों ने इस माह के शुरू में भी सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। तब एक मिसाइल से इस पर हमला किया था। इसमें 26 लोग घायल हुए थे। हाउती विद्रोहियों ने इस माह के शुरू में सऊदी अरब की 20 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया था। ये सैन्य चौकियां यमन की सीमा से लगे सऊदी अरब के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत नजरान में बताई गई थीं।

आइएस बंदियों के पक्ष में यूएन मानवाधिकार प्रमुख

जिनेवा, रायटर : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बचेलेट आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़ाव रखने पर सीरिया और इराक में बंदी बनाए गए करीब 55 हजार लोगों के पक्ष में खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इन बंदियों पर निष्पक्ष मुकदमा चलाया जाए या फिर इन्हें रिहा किया जाए।

मिशेल ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा कि देशों को अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आतंकियों के बच्चों को यह दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि वे किसी देश के नागरिक नहीं हैं। वे पहले से ही समस्याओं में घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा, 'करीब 50 देशों के संदिग्ध विदेशी आतंकियों समेत 55 हजार लोगों और उनके 11 हजार पारिवारिक सदस्यों को पूर्वोत्तर सीरिया के अल-अल कैंप में बंदी बनाकर रखा गया है। यहां बेहद बदतर हालात हैं। निष्पक्ष ट्रायल के जरिये समाज को कट्टरता और हिंसा के खतरे से सुरक्षित किया जाना चाहिए और कानून के अभाव में उन लोगों को बंदी बनाए रखना स्वीकार्य नहीं है, जिन पर कोई अपराध करने का संदेह न हों।' अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स (एसडीएफ) ने सीरिया में बचे आइएस के अंतिम गढ़ पर पिछले साल नियंत्रण पा लिया था। इसके बाद से ही पूर्वोत्तर सीरिया के अधिकारी पश्चिमी देशों से यह आग्रह कर रहे हैं कि वे आइएस से जुड़ने वाले अपने नागरिकों और उनके रिश्तेदारों को वापस ले लें। लेकिन एक-दो देशों को छोड़ कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। आइएस ने साल 2014 में सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब इस आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए दुनिया के कई देशों के नागरिक इन देशों में पहुंचे थे।

मिशेल बचेलेट। फाइल

बांग्लादेश में ट्रेन हादसा, पांच की मौत

बांग्लादेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित मौलवी बाजार के कुलौरा में रोमाचल पुल पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की बोगियां। रायटर

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं 67 लोग घायल हो गए। रविवार को यह हादसा उस समय हुआ जब सिलहट से ढाका जाने वाली उपबन एक्सप्रेस के पांच डिब्बे मौलवी बाजार में पटरी से उतर गए। इनमें से दो कोच नहर में गिर गए। दुर्घटना से सिलहट और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल सेवा बाधित हो गई। मौलवी बाजार के सिविल सर्जन शाहजहां कबीर ने बताया कि ट्रेन हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है। इनमें दो महिलाएं और तीन पुरुष हैं। घायलों में 20 की हालत गंभीर है। सभी का इलाज सिलहट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अग्निशमन सेवा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मदद के लिए बचाव दल की 11 इकाइयां पुलिस कर्मियों के साथ दुर्घटनास्थल पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं।

उभरते भारत से संबंध बनाने में पिछड़ रहा ब्रिटेन

- ब्रिटिश संसद ने लगाई सरकार को लताड़

लंदन, प्रेट्र : वैश्विक मंच पर उभर रहे भारत से ब्रिटेन फायदा नहीं उठा रहा। वह भारत के साथ संबंधों के विकास वाले कदम उठाने में पिछड़ रहा है। यह बात ब्रिटिश संसद की एक रिपोर्ट में कही गई है।

ब्रिटेन और भारत के संबंधों के पुनर्निर्माण पर आई रिपोर्ट- बिल्डिंग ब्रिजेज : रीवेकनिंग यूके-इंडिया टाइज, यूके-इंडिया वीक 2019 के दौरान आई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के साथ संबंधों को नया रूप देने के लिए भारतीयों के वास्ते अनुकूल वीजा और इमीग्रेशन नीतियां बनाए जाने की जरूरत है। ये नीतियां भारतीय पर्यटकों, छात्रों और पेशेवरों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में भारत के साथ संबंधों के विकास के अवसर खोने के लिए सरकार को आरोपित किया गया है। कहा गया है कि उभर रहे भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने में ब्रिटेन अन्य देशों की तुलना में पिछड़ रहा है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन ने संबंध मजबूत बनाने के कई मौके गंवाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यावहारिक कदम उठाकर सरकार भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए भारतीयों के ब्रिटेन में आने, पढ़ने और काम करने की सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत होगी। वीजा मामले में भारतीयों पर वही कड़े नियम लागू होते हैं जो अलोकतांत्रिक देश चीन के नागरिकों पर लागू होते हैं, इस पर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। भारतीय छात्रों को आकर्षित करने वाली नीति न होने पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि छात्रों से अर्थव्यवस्था के विकास में भले ही खास मदद न मिलती हो लेकिन उनसे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इसलिए सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाला विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय निश्चित करे कि भारत के साथ किन तरीकों से सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन के संबंध मजबूत हों। इसके लिए वह नीतियों में बदलाव की रूपरेखा का प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे।

चिंताजनक

टेंटों में पड़ा है ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने-पीने के सामान के पैकेट और रस्सियों का ढेर, इस सीजन में चोटी पर पहुंचे थे रिकॉर्ड पर्वतारोही

दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट पर लगा कचरे का ढेर

काठमांडू, एपी : नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर इस सीजन में रिकार्ड संख्या में पर्वतारोही चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कचरे का ढेर जमा हो गया है। इसकी सफाई में जुटे एक सरकारी दल को यह समझ में नहीं आ रहा है कि खाली पड़े टेंटों से लेकर मानव अपशिष्ट को किस तरह हटाया जाए।

एवरेस्ट की सफाई करने में सरकार की मदद करने वाले शेरपाओं का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों, खाने-पीने के सामान के पैकेट और रस्सी का ढेर लगा हुआ है। एवरेस्ट की चोटी से नीचे यानी आठ हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिविर संख्या चार या साउथ कर्नल पर टेंटों का कचरा फैला हुआ है। एवरेस्ट पर पिछले माह एक सफाई अभियान का नेतृत्व करने वाले शेरपा दावा स्टीवन ने कहा, 'इस ऊंचाई से कम ऑक्सीजन, फिसलन भरे ढलानों और खराब मौसम के बीच टेंट जैसे सामान को नीचे लाना बेहद मुश्किल काम है।' स्टीवन माउंट एवरेस्ट की सफाई करने में पिछले 12 साल से जुटे हुए हैं।

एवरेस्ट की सफाई करने के बाद कूड़ा एकत्र करते नेपाल सेना के जवान। एपी

700 पर्वतारोही पहुंचे एवरेस्ट (8,848 मीटर) पर इस साल 14 मई से शुरू हुए सीजन में अब तक 700 से ज्यादा पर्वतारोहियों के पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में पर्वतारोहियों के आने से नेपाली शेरपा भी चकित हैं। शेरपा विदेशी पर्वतारोहियों के लिए गाइड का काम करते हैं। वह उनके लिए एवरेस्ट पर चढ़ने का मार्ग तैयार करते हैं।

पांच हजार किलोग्राम कचरा होने का अनुमान

एवरेस्ट पर शिविर संख्या चार पर 30 टेंट और करीब पांच हजार किलोग्राम कचरा होने का अनुमान है। हालांकि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि पूरे एवरेस्ट पर कितना कचरा है? यह तभी दिखाई देगा जब बर्फ पिघलेगी।

इस कारण भी होती है गंदगी

एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कुछ पर्वतारोही अस्थायी टॉयलेट का प्रयोग नहीं करते हैं। वे बर्फ में गढ्डा बनाकर कर शौच करते हैं और कचरे को दरारों में फेंक देते हैं। हालांकि तापमान बढ़ने पर ग्लेशियर जब पिघलते हैं, तब ये कचरा भी बहकर नीचे आता है। इस तरह के कचरे से पानी के दूषित होने का खतरा रहता है। एवरेस्ट के आधार शिविर में रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल पीने के पानी के तौर पर करते हैं।

हंट ने जॉनसन को कायर बताया

- कहा, ब्रेक्जिट पर बहस से बच रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री
- घरेलू विवाद के बाद बोरिस की लोकप्रियता में कमी

लंदन, रायटर : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पाने के लिए चल रहे मुकाबले में जुबानी जंग जारी है। मुकाबले में आगे निकलने की कोशिश में विदेश मंत्री जर्मी हंट ने सोमवार को अपने प्रतिद्वंद्वी व पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन पर तीखा हमला किया। कहा, बोरिस कायर हैं। वह ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव) पर सार्वजनिक बहस से बच रहे हैं। बोरिस नहीं बताना चाहते कि ब्रेक्जिट पर वह क्या करेंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रेक्जिट के लिए संसद में प्रस्ताव पारित न करा पाने के कारण ही टेरीजा मे को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है।

हंट ने कहा, बहस के सवाल पर वह (बोरिस) कायर हैं। स्काई टेलीविजन पर बहस का मौका मिलने पर उन्होंने जिस तरह से मुंह मोड़ा है वह बोरिस के लिए खासा अशोभनीय है। लोग जानना चाहते हैं कि खास मसलों पर आप क्या करेंगे। उनसे निपटने की क्या योजना है। हंट ने कहा, बोरिस से वादा करते हैं कि इस लड़ाई में वह उन्हें हराएंगे। हंट ने कहा, वह बेहतर शर्तों के साथ ब्रेक्जिट को पूरा करेंगे।

उल्लेखनीय है कि जिस भी उम्मीदवार को कंजरवेटिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों में से अधिकांश का समर्थन हासिल होगा, वही प्रधानमंत्री बन सकेगा। एक सप्ताह पहले बोरिस जॉनसन की जीत की संभावना 92 प्रतिशत थी, जो बीते सप्ताह घटकर 79 प्रतिशत रह गई। उन्होंने किसी भी कीमत पर 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा करने का एलान किया है।

गुरुवार देर रात उनके आवास पर पुलिस जाने के बाद आई। महिला मित्र के साथ झगड़े और तोड़फोड़ की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। पुलिस को दोनों ने सब कुछ ठीक बताया लेकिन विवाद के सार्वजनिक होने के बाद बोरिस की लोकप्रियता पर असर पड़ा। शनिवार को बर्मिंघम पत्रकारों ने जब इस बाबत सवाल पूछा तो बोरिस ने जवाब नहीं दिया।